

राजकोषीय प्रोत्साहन

साभार: इंडियन एक्सप्रेस
(26 सितम्बर, 2017)

सौम्या कांति घोष (मुख्य आर्थिक सलाहकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया),
अजित रानाडे (मुख्य अर्थशास्त्री, आदित्य बिड़ला समूह)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

यह आलेख आवश्यक क्यों है? : इस आलेख में राजकोषीय विस्तार को लेकर व्याप्त चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि अभी तक राजकोषीय प्रोत्साहन की बात अर्थशास्त्रियों के बीच चिंता का विषय रहा है। यहां तक कि नीति निर्माताओं ने राजकोषीय विस्तार को आगे बढ़ाने के दौरान रक्षात्मक आवाज शुरू कर दी है।

हालांकि, ऐतिहासिक रूप से यह शब्द भारत में संदर्भ के बाहर उद्धृत किया गया है और वर्तमान बहस भी कोई भिन्न नहीं है। यहां तक कि जब बात है कि सरकार विकास का समर्थन करने के लिए राजकोषीय ध्यानाकर्षण की योजना बना रही है, तो मजबूत असंतोषपूर्ण आवाजों का सुझाव है कि इससे स्थिति और भी खराब हो जाएगी। देखा जाये तो यह तुलना वर्ष 2008 के प्रोत्साहन के साथ किए जा रहे हैं और गंभीर चेतावनी जारी की जा रही है। हम मानते हैं कि वर्तमान स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए और वर्ष 2008 और वर्तमान स्थिति के बीच उचित तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक काउंटर-चक्र्रीय राजकोषीय नीति विस्तार पर अच्छे से विचार किये जाने कब आवश्यकता है और इसे अतीत की गलत दिशा में राजकोषीय नीति के समान गलत नहीं समझा नहीं जाना चाहिए।

सबसे पहले, आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं, संख्याओं को संदर्भ में डालते हैं। 2008-2010 के दौरान भारत द्वारा दिए गए विवेकाधीन वित्तीय उत्तेजना का कुल आकार सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत था, जो एशियाई समकक्षों और कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम था, अर्थात् कोरिया 9.4 प्रतिशत, अमेरिका 4.9 प्रतिशत, चीन में 6.2 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका, 6.8 प्रतिशत। दरअसल यह समस्या उस वक्त मुद्रास्फीति और रुपए के गिरने के पीछे मुख्य अपराधी नहीं था, जैसा कि कुछ आलोचकों का मानना है। जीडीपी के 0.9 प्रतिशत, वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले ऋण माफी सहित जीडीपी का लगभग 0.8 प्रतिशत और एमएसपी में वित्त वर्ष 2011 के दौरान 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अतिरिक्त उपाय किए गए थे, जो एक साथ जिम्मेदार थे, इस गिरावट के लिए, न कि सिर्फ फिस्कल स्टिमुलस (राजकोषीय प्रोत्साहन)।

दूसरा, तब और अब के बीच एक महत्वपूर्ण मतभेद है, विशेष रूप से ऋण छूट में (विभिन्न राज्यों द्वारा, केन्द्र द्वारा नहीं)। लेकिन स्थिति अब काफी अलग है। जिसमें सबसे पहला यह है कि वेतन आयोग की सिफारिशें बढ़ी हुई पीएफसीई (निजी अंतिम पूंजी व्यय) के एक प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष 2009 में 22 प्रतिशत से वित्त वर्ष 17 में 9 प्रतिशत घट गयी। इसका मतलब हुआ खपत में कमी। दूसरा, पहले के वर्षों के विपरीत, कोई बकाया मौजूद नहीं है जिसका भुगतान करना शेष हो। तीसरा, ऋण छूट, मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी, इसकी संभावना बहुत कम है, जैसे कि मुद्रास्फीति पिछले तीन सालों में दो अंकों से कम अंक के लिए ढांचागत रूप से सही हो चुकी है और ग्रामीण मांग कई वर्षों के अपने निचले स्तर पर आ गयी है। चौथा, पिछले तीन वर्षों में खरीद मूल्य में वृद्धि बढ़ी है और मुद्रास्फीति को इससे खतरा भी नहीं है।

राजकोषीय विस्तार को हमेशा बदनामी का समाना करना पड़ा है, क्योंकि भारत में यह काफी हद तक चक्र्रीय राजकोषीय नीति रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि राजकोषीय नीति उच्च समय में विस्तारित रहती है (करों को कम करने/घटाने में वृद्धि) और मंदी में संकुचित रहती है। यह काउंटर-चक्र्रीय नीति के विपरीत रहती है, जो अधिक प्रभावी है। वर्ष 1990 के दशक के मध्य पूर्व एशियाई संकट के बाद से, आईएमएफ जैसी संस्थाओं ने विकासशील देशों के लिए फिस्कल ऑस्टेरिटी (राजकोषीय घाटे के आकार में कटौती) को बढ़ावा दिया, खासकर जब कर्ज की स्थिति खराब हो गई या राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय सीमा से पार हो गया। रेटिंग एजेंसियां भी एक ही स्वर में मांग करने लगी और कहा कि बढ़ते कर्ज और घाटे से निपटने के लिए फिस्कल ऑस्टेरिटी आवश्यक हैं। हालांकि, यूरोपीय ऋण संकट के दौरान इस तरह की सलाह को तुरंत त्याग दिया गया था। आईएमएफ ने भी माफी मांगी कि फिस्कल ऑस्टेरिटी की इसकी पूर्व सलाह एक गलती थी। मलेशिया, जिसने वर्ष 1997 में आईएमएफ की उपेक्षा की थी, बाद में यह उसकी आखिरी हंसी बन कर रह गयी। तो जाहिर है, एक प्रभावी नीति एक क्लासिकल कीनेसियन दृष्टिकोण की मांग करती है, अर्थात् काउंटरस्टिकल राजकोषीय नीति। इसका मतलब यह है कि जब अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के दौरान बढ़ रही है और वृद्धि हो रही है तो घाटे में कमी आ सकती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग और बजट प्रबंधन पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कर्ज और घाटे के लिए संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लेकिन यह घाटे लक्ष्य से जीडीपी के 0.5 प्रतिशत तक विचलित करने के लिए दूर जाने का प्रावधान (escape clause) प्रदान करता है। एस्केप क्लॉज के लिए एक ट्रिगर अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित राजकोषीय प्रभाव के साथ ढांचागत सुधार था। इसलिए निश्चित रूप से जीएसटी और आरईआरए को तत्काल रूप में स्थापित करने से पहले इसके मानदंड के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अल्पकालीन राजकोषीय अनिश्चितता का निर्माण किया है।

इसलिए, यह जरूरी है कि हम मानते हैं कि सरकार को राजकोषीय विस्तार के लिए कोशिश करेगी। इस तरह यह वर्ष 2009 से भिन्न है। नीति निर्माताओं को अब उपभोक्ताओं के हाथों में पैसा देने के बजाये संरचनात्मक बाधाओं पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यापक रूप से चर्चा वाले पुनर्पूजीकरण बंधनों के माध्यम से पुनर्पूजीकरण करना चाहिए, जो कि न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों (उदाहरण के लिए कोरिया और मलेशिया) में मौजूद हैं। ऐसे बांड के स्पष्ट लाभ यह है कि इससे राजकोषीय गणित नहीं बदलता है। सरकार को तत्काल कर राजस्व बढ़ाने की जरूरत नहीं है और बाजारों के बजाय सीधे बैंकिंग प्रणाली से उधार लेने की जरूरत है, केंद्र निजी उधार की भीड़ को बाहर कर सकता है या बाजार की उपज विकृत कर सकता है।

राजकोषीय पैकेज में क्षेत्र-विशिष्ट उपाय भी शामिल हो सकते हैं, जैसे निर्यात, दूरसंचार, निर्माण और बिजली जैसे क्षेत्र। मजदूरी लागत और ब्याज की रोकथाम के समर्थन के लिए पिछले साल के टेक्सटाइल पैकेज का विस्तार किया जा सकता है। कुछ सफल राज्य स्तर की पहल, जैसे ओडिशा के परिधान क्षेत्र में, राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जा सकता है। किफायती आवास एक और बड़ा अवसर प्रदान करता है इसमें एक बड़ा गुणक प्रभाव है जो निर्माण क्षेत्र में मदद कर सकता है और अधिकतम रोजगार का निर्माण कर सकता है। विवादित संपत्तियों पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जहाँ सरकार को इस एजेंडे पर कार्य करते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

संरचनात्मक और गहन सुधार जैसे जीएसटी, आरईआरए, मौद्रिक नीति ढांचे और कैशलेस तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए कदम, सभी लम्बी अवधि तक लाभ प्रदान करेंगे। हालांकि, इन्होंने अल्पकालिक अनिश्चितताएं और विघटन का निर्माण किया है। इसे निपुण नीति और धारणा प्रबंधन की आवश्यकता है। पूर्व एनडीए सरकार ने फिक्स्ड फीस से आय हिस्सेदारी के लिए दूरसंचार नीति में सुधार लाने और सुनहरी चतुर्भुज परियोजना शुरू करने जैसे बेहतर फैसले अपनाये हैं, जो सभी लंबे समय तक लाभ प्रदान करते रहेंगे, जिससे 9 प्रतिशत से अधिक की निरंतर वृद्धि संभव हो सकती है। साथ ही इससे लघु अवधि के वित्तीय उपाय भी मध्यम अवधि में फल देंगे।

भूमि और श्रम बड़े सुधार का इंतजार कर रहा है, साथ ही शहरी बुनियादी ढांचे बड़े निवेश का इंतजार कर रहा है। भारत को क्षेत्रीय विकास में असंतुलन और शहरी-ग्रामीण विभाजन को सही करने और कृषि क्षेत्र की समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत है। इसे बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करना बाकि है, लेकिन केवल इस वर्ष के सन्दर्भ में सोचे तो हमें निश्चित रूप से राजकोषीय को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

क्या है राजकोषीय घाटा?

- सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिये कितनी उधारी की जरूरत होगी। कुल राजस्व का हिसाब-किताब लगाने में उधारी को शामिल नहीं किया जाता है। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है।
- पूंजीगत व्यय लंबे समय तक इस्तेमाल में आने वाली संपत्तियों जैसे-फैक्टरी, इमारतों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों पर होता है। राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर केंद्रीय बैंक (रिजर्व बैंक) से उधार लेकर की जाती है या इसके लिये छोटी और लंबी अवधि के बॉन्ड के जरिये पूंजी बाजार से फंड जुटाया जाता है।

बढ़ता राजकोषीय घाटा चिंता का विषय क्यों?

- अर्थशास्त्री और अन्य नीति निर्माता अक्सर इस बात पर सहमत नजर आते हैं कि बड़ा और निरंतर बरकरार बजट घाटा बेहतर आर्थिक प्रदर्शन के आड़े आ जाता है। ऐसे घाटों की वजह से निजी निवेश बाहर जाता है, मुद्रास्फीति का दबाव बनता है, भुगतान संतुलन कमजोर पड़ता है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना मुश्किल होता जाता है और आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है।

मौजूदा अर्थव्यवस्था के अनुकूल कुछ बिंदु:

- मुद्रास्फीति सामान्यतः मध्यम स्तर पर ही रही है और इसने हाल ही में 1.5% के निम्नतम स्तर को छुआ है।
- व्यापार और राजकोषीय घाटा दोनों ही मध्यम स्तर के और नियंत्रण योग्य रहे हैं।

- पिछले डेढ़ वर्षों में ब्याज दर में लगातार कमी की गई है।
- वित्तीय बाजारों (स्टॉक और बॉन्ड) और प्रत्यक्ष निवेश के रूप में डॉलर का आना लगातार जारी है।
- शेयर बाजार का सूचकांक अब तक के उच्चतम स्तर पर है।
- पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तुलनात्मक रूप से स्थिर हैं।
- बेहतर मानसून से कृषि उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएँ बढ़ गई हैं।

वृद्धि दर में गिरावट:

- वृद्धि की अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था उन्हें उच्च वृद्धि दर का रूप देने में सफल नहीं रही है। यहाँ तक कि अर्द्ध-वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात की ताक़ीद की गई थी कि वृद्धि दर में 1 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। दरअसल वृद्धि दर में 1% का घाटा बहुत मायने रखता है।

गिरावट के कारण

- जानकारों के अनुसार वृद्धि दर में गिरावट की प्रमुख वजह उद्योग क्षेत्र के निराशाजनक प्रदर्शन से है, जो पिछले साल 7.4% की तुलना में 1.6% पर आ गई है। पिछली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन में 3.1% की वृद्धि हुई थी।
- विश्लेषकों ने गत पाँच वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र के लिये इसे सबसे खराब तिमाही माना है। विनिर्माण क्षेत्र ने पिछली तिमाही में 5.3% की तुलना में इस बार 1.2% की वृद्धि दर्ज की और पिछले साल की इसी तिमाही में यह 10.7% थी।
- खनन गतिविधियों में भी पिछली तिमाही में 6.4% की वृद्धि के मुकाबले इस बार 0.7% की गिरावट आई है। सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, परंतु कृषि क्षेत्र ने निराश किया है।

संभावित प्रश्न

“हमारी नीति पुनर्पूँजीकरण बैंकों पर केन्द्रित होनी चाहिए, जहाँ दूरसंचार और आवास जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन और गतिशीलता प्रदान की जाये और जीएसटी तथा विमुद्रीकरण से होने वाले विघटन को कम किया जा सके।” इस कथन का विश्लेषण करें।

(200 शब्द)